

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए विभागीय संकल्प सं०-590, दिनांक-27.03.2017 के आलोक में राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों के लिए कौंसवार शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Tuition fee and Other Compulsory Non-Refundable Fee) अधिकतम सीमा निम्नवत् है :-

Course#	Course	Maximum Limit in Rs.
1	Degree in Medicine	15000
2	Post Graduate in Medicine	15000
3	Degree in Engineering	15000
4	Post Graduate in Engineering	15000
5	Degree in Computer Science / Applications	15000
6	Post Graduate in Computer Science / Applications	15000
7	Degree in Planning	15000
8	Post Graduate in Planning	15000
9	Degree in Architecture	15000
10	Post Graduate in Architecture	15000
11	Degree in Design	15000
12	Post Graduate in Design	15000
13	Degree in Fashion Technology	15000
14	Post Graduate in Fashion Technology	15000
15	Degree in Agriculture	5000
16	Post Graduate in Agriculture	5000
17	Degree in Veterinary & Allied Sciences	15000
18	Post Graduate in Veterinary & Allied Sciences	15000
19	Degree in Management	15000
20	Post Graduate in Management	15000
21	Degree in Business Finance / Administration	15000
22	Post Graduate in Business Finance / Administration	15000
23	Post Graduate Diploma Courses in Various Branches of Management	15000
24	Post Graduate Diploma Courses in Various Branches of Medicine	15000
25	C.A. / I.C.W.A. / C.S. / I.C.F.A. Etc	15000
26	M.Phil, Ph.d and Post Doctoral Programs (D.Lit, D.sc, etc)	5000
27	L.L.B, Integrated L.L.B, L.L.M	15000
28	Professional Courses leading to degree	15000
29	Diploma Certificate in B.Pharm	10000
30	Diploma Certificate in B.Nursing	10000
31	Diploma Certificate in B.FS	10000
32	Diploma Certificate in rehabilitation	10000
33	Diploma Certificate in diagnostics	10000
34	Diploma Certificate in mass communication	10000
35	Diploma Certificate in Hotel Management & Catering	10000
36	Diploma Certificate in Travel/Tourism/Hospitality Management	10000
37	Diploma Certificate in Interior Decoration	10000
38	Diploma Certificate in Nutrition & Dietetics	10000
39	Diploma Certificate in Commercial Arts	10000
40	Diploma Certificate in Financial Services ( Banking, Insurance, Taxation etc)	10000
41	Vocational courses where entrance qualification is Class XII or above	10000
42	ITI courses and Polytechnic where entrance qualification is Class XII or above	10000
43	Post Graduate in arts, science, commerce, pharma & education etc and Post Graduate Courses not covered under Group-I & Group II	5000
44	Degree in arts, science & commerce etc and other Graduate Courses	5000
45	Senior Secondary(10+2) Level courses in Arts, Science, Commerce and Others	2000
46	ITI Courses Which entrance Qualification is Class X	5000
47	3 Years Diploma Courses in Polytechnic which entrance qualification is Class X	10000
48	P.H.D.	5000
49	Pharm.D. (Doctor of Pharmacy)	15000
50	Diploma in Pharmacy (D. Pharm)	10000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य के अंदर से सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए संस्थान से निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति की राशि अनुमान्य की जाएगी।</li> <li>राज्य के बाहर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए संस्थान से निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति की राशि अनुमान्य की जाएगी।</li> <li>राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान से निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति की राशि अनुमान्य की जाएगी।</li> <li>उक्त की अलावा मास सरकार द्वारा निर्धारित Maintenance Allowance/Academic Allowance देय होगा जिसकी विवरणी संलग्न है।</li> </ul>	

बिहार सरकार  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषय - वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देश के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से नवीकरण छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत निर्धारित दर पर ही, छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

यह योजना राज्य के अन्दर एवं बाहर देश के अंतर्गत सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 1,00,000/- तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

2- प्रायः देखा जाता है कि मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क समाज के कमजोर वर्गों के छात्र/छात्राओं के पहुँच के बाहर रहता है। उक्त स्थितियों के कारण संबंधित छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम राशि के अभाव में बाधित नहीं हो इसलिए छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने की आवश्यकता है।

3- अतः अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देश के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के नवीकरण छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत निर्धारित दर पर ही छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में सम्यक् विचारोंपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

(क) भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के अन्दर सभी सरकारी संस्थानों एवं राज्य के बाहर देश के अंतर्गत सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क संबंधित राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर अनुमान्य किया जायेगा।

(ख) भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के अन्दर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में संचालित कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षण

शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (अधिकतम सीमा रू० 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार निम्नवत् दिया जायेगा :-

क्र०	कोर्स की विवरणी	छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क + अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1	विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इंटरमीडियट कक्षा यथा-आई०ए० / आई०एस०सी / आई०कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	रू० 2000/-
2	स्नातक स्तरीय कक्षा यथा बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	रू० 5000/-
3	स्नातकोत्तर कक्षा यथा-एम०ए/एम०एस०सी/एम०कॉम/एम०फिल/पी०एच०डी० एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	रू० 5000/-
4	आई०टी०आई	रू० 5000/-
5	त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पॉलिटेक्निक एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	रू० 10000/-
6	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा-इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबंधन तथा अन्य समकक्ष कोर्स (कृषि को छोड़कर)।	रू० 15000/-

(ग) वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी संस्थानों (यथा आई०आई०टी, तथा एन०आई०टी में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम क्रमशः रू० 90,000/- तथा रू० 70,000/- की दर) एवं अन्य केन्द्रीय सरकारी संस्थानों, यथा-नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन०आई०एफ०टी०, जे०आई०पी०एम०ई०आर०, ए०आई०आई०एम०एस आदि में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम रू० 75,000/- की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतान होगा।

(घ) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं की तुलना में सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ङ) उपर्युक्त के अतिरिक्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसंधान भत्ता एवं अन्य भत्ता नियमानुसार देय होगा।

(च) इस संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2014 दिनांक-21.08.2015 को विलोपित किया जाता है।

4- इस छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित संस्थानों एवं उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन एवं प्रासंगिक अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही किया जायेगा। समुचित रूप से गठित जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी, जिसका भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

5- तदनुसार इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/संकल्प ज्ञापांक इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

6- इस सम्बन्ध में योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मौणा)

सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 27/03/17

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (2 प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 27/03/17

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 27/03/17

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

प्रतिलिपि- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को संकल्प की दो हार्ड प्रतियों एवं सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 1500 (एक हजार पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 27/03/17

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, कल्याण /सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी कोषागार

-4-

पदाधिकारी/सगी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

पटना, दिनांक- 27/03/17

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम बिहार पटना/उप सचिव/अवर सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

पटना, दिनांक- 27/03/17

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट <http://bcebcwelfare.bih.nic.in> पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

पटना, दिनांक- 27/03/17

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

पटना, दिनांक- 27/03/17

प्रतिलिपि- माननीय उपमुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

पटना, दिनांक- 27/03/17

प्रतिलिपि- सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015- 590

पटना, दिनांक- 27/03/17

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

**Centrally Sponsored Scheme of  
Post-Matric Scholarship for OBC Students for studying in India**

(Revised w.e.f. September 2018)

**Scheme Guidelines:**

**I. OBJECTIVE**

The objective of the scheme is to provide financial assistance to the OBC students studying at post-matriculation or post-secondary stage to enable them to complete their education.

**II. SCOPE**

These scholarships shall be available for studies in India only and will be awarded by the Government of State/Union Territory to which the applicant actually belongs, i.e. permanently settled.

**III. CONDITIONS OF ELIGIBILITY**

- i. The scholarships will be open to Indian nationals belonging to OBCs, as notified by the Central Govt./State Govt./ UT Admn.;
- ii. These scholarships will be given for the study of all recognized post-matriculation or post-secondary courses pursued in recognized institutions as specified in para IV(i).
- iii. Only those candidates who belong to OBCs so specified in relation to the State/UT to which the applicant actually belongs, i.e. permanently settled and who have passed the Matriculation or Higher secondary or any higher examination of a recognized University or Board of Secondary Education will be eligible.
- iv. Candidates who, after passing one stage of education, are studying in the same stage of education in different subject e.g. I. Sc. after I.A or B.Com. after B.A. or M.A. in a subject after M.A in another subject will not be eligible.
- v. Students who, after having completed their educational career in one professional line, e.g., LLB after B.T/B. Ed will not be eligible.
- vi. Students studying in XI Class of the Higher Secondary School courses or the XII class of the Multipurpose High School will not be eligible for it being a continuous school course. However, in cases, where tenth class examination of such courses is treated as equivalent to Matriculation and students who after passing tenth class join other courses, such students will be treated as post-matric students and will be eligible for the award of scholarships.
- vii. Students pursuing Post-graduate courses in medicine will be eligible only if they are not allowed to practice during the period of their course.
- viii. Students who after failing or passing the Under Graduate/Post-Graduate examinations in Arts/Science/Commerce join any recognized professional or Technical certificate/diploma/degree courses will be awarded scholarships if otherwise eligible. No subsequent failure will be condoned except for courses in Group 'A' and no further change in the course will be allowed thereafter.
- ix. Students who pursue their studies through correspondence courses will be eligible towards reimbursement of non-refundable fee. The term correspondence includes distant and continuing education. Besides reimbursement of non-refundable fee, such students will also be eligible for an annual allowance of Rs. 900/- for essential/prescribed books, as applicable.

- x. Scholarships should be restricted upto two boys of the same parents/ This restriction will, however, not apply to girls.
- xi. A scholarship holder under this Scheme will not hold any scholarship/stipend. If awarded any other scholarship/stipend, the students exercise his/her option for either of the two scholarships/stipends, whichever is more beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution about the option made. No scholarship will be paid to the students under this Scheme from the date he/she accepts any other scholarships/stipend. The student can however, accept free lodging or a grant or ad-hoc monetary help from the State Government or any other source for the purchase of books, equipment or for meeting the expenses on board and lodging, in addition to the scholarship amount paid under the Scheme.
- xii. Scholarship holders who are receiving coaching in any of the pre-examination training centers with financial assistance from the Central Government/State Government will not be eligible for stipend under the coaching schemes for the duration of the coaching programme.
- xiii. Employed students whose income combined with the income of their parents/guardians does not exceed Rs. 1.50 lakh per annum shall be eligible for post-matric scholarship to the extent of reimbursement of all compulsorily payable non-refundable fee.
- xiv. Unemployed students whose parents/guardians income from all sources does not exceed Rs. 1.50 lakh per annum will be entitled for the scholarship under the Scheme.

**Note 1:** So long as either of the parents (or husband in the case of married unemployed girl students) are alive, only income of the parents/husband, as the case may be, from all sources has to be taken into account and of no other members even though they may be earning. In the form of income declaration, income is to be declared on this basis. Only in the case where both the parents or husband in the case of married but unemployed girl student have died, the income of the guardian who is supporting the student in his/her studies has to be taken into consideration. Such students whose parent's income is affected due to death of one of earning parents and resultanty comes within the income ceiling prescribed under the scheme, shall become eligible for scholarship, subject to their fulfilling other conditions of eligibility, from the month in which such death takes place. The applications for the scholarship from such students can be considered even after lapse of last date of receipt of applications, on compassionate grounds.

**Note 2:** House Rent Allowance received by the parents of a student be exempted from the computation of 'income' if the same has been permitted to be exempted for purpose of Income-Tax.

**Note 3:** Income Certificate is required to be taken once only, i.e. at the time of admission of courses, which are continuing for more than one year.

#### **IV. VALUE OF SCHOLARSHIP**

The value of scholarship will include Maintenance Allowance, Reader Charges for blind students, reimbursement of compulsory non-refundable fee, Study Tour Charges/thesis typing/printing charges and book allowance for students pursuing correspondence course, for complete duration of the course as per details given below:-

**i) Maintenance Allowance**

Course of (1)	(Rs. Per Month) Rate of Maintenance Allowance	
	Hostellers (2)	Day Scholars (3)
<b>Group-A</b>		
(i) Degree and Post Graduate level courses including M.Phil., Ph.D. and Post Doctoral research in Medicine (Allopathic, Indian and other recognized systems of medicines), Engineering, Technology, Planning, Architecture, Design, Fashion Technology, Agriculture, Veterinary & Allied Sciences, Management, Business Finance/ Administration, Computer Science/Applications.	750	350
(ii) Commercial Pilot License courses from GOI Institutes (including helicopter pilot and multiengine rating) (Maximum 20 slots per annum) - In addition to maintenance allowance, an amount of Rs.5,000/- per flying hour for maximum 200 hours will be paid by the State Govt./UT with the approval of the Government of India,		
(iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of management & medicine.		
(iv) C.A./I.C.W.A./C.S./I.C.F.A. etc.		
(v) M. Phil., Ph.D. and Post-Doctoral Programmes (D. Litt., D.Sc. etc.)		
(vi) L.L.M.		
<b>Group-B</b>		
(i) Graduate/Post/Graduate courses leading to Degree, Diploma, Certificate in areas like Pharmacy (B. Pharma), Nursing (B Nursing), LLB, BFS, other paramedical branches like rehabilitation diagnostics etc., Mass Communication, Hotel Management & Catering, Travel/Tourism/Hospitality Management, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Art, Financial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2).	510	335
(ii) Post Graduate courses not covered under Group A e.g. MA/M.Sc./M.Com/ M.Ed./M.Pharma etc.		
<b>Group-C</b>		
All other courses leading to a graduate degree not covered under Group A & B e.g. BA/B.Sc./B.Com etc.	400	210



**Group-D**

All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificate (class XI and XII); both general and vocational stream, ITI courses, 3 year diploma courses in Polytechnics, etc.

260

160

**Note :** Scholars who are entitled to free boarding and/or lodging will be paid maintenance charges at 1/3rd of hostellers' rate.

**ii) Reader Charges for blind students (Blind Scholars)**

The blind scholars will be given additional amount as 'Readers Charges' as mentioned below:-

Group	Reader Allowance (Rs. P.m.)
Group A,B	175
Group C	130
Group D	90

**iii) Fees**

Scholars will be paid enrolment/registration, tuition, games, union, library, magazine, medical examination and such other fees compulsorily payable by the scholar to the institution or University/Board. Refundable deposit-like caution money, security deposit will, however, be excluded.

**iv) Study Tours**

Study tour charges upto a maximum of Rs. 900/- per annum limited to the actual expenditure incurred by the student on transportation charges etc., will be paid to the scholars studying professional and technical courses, provided that the head of the institution certifies that the study tour is essential for the scholar for completion of his/her course of study.

**v) Thesis Typing /Printing charges**

Thesis typing/printing charges upto a maximum of Rs. 1000 will be paid to research scholars on the recommendation of the Head of the Institution.

## SELECTION OF CANDIDATES

All the eligible Other Backward Classes candidates will be given scholarships subject to the condition of eligibility prescribed in para III of this Scheme. Candidates belonging to one State, but studying in another State, will be awarded scholarship by the State to which they belong and will submit their applications to the competent authorities in that State. In the matter of exemption from fee or other concessions also, they will be treated as studying in their own State.

## VI. DURATION AND RENEWAL OF AWARDS

- i. The award once made will be tenable from the stage at which it is given to the completion of course subject to good conduct and regularity in attendance. It will be renewed from year to year if the course is continuing for a number of years, the scholar secures promotion to the next higher class irrespective of the fact whether such examinations are conducted by a University or the Institution.
- ii. If an OBC scholar is pursuing Group A course fails in the examination for the first time, the award may be renewed. For second and subsequent failures in any class the student shall bear his/her own expenses until he/she secures promotion to the next higher class.
- iii. If a scholar is unable to appear in the annual examination owing to illness and or on account of any other unforeseeable event, the award may be renewed for the next academic year on submission of medical certificate and/or other required sufficient proof to the satisfaction of the Head of the Institution and his/her certifying that the scholar would have passed had he appeared in the examination.
- iv. If according to the Regulations of a University/Institution, a student is promoted to the next higher class even though he/she may not have actually passed in lower class and is required to take examination of the junior class again after sometime, he/she will be entitled to scholarship for the class to which he/she is promoted if the student is otherwise eligible for scholarship.

## VII. PAYMENT

- i. Maintenance charges shall be payable from 1<sup>st</sup> April or from the month of admission, whichever is later, to the month in which the examination are completed at the end of the academic year (including maintenance during holidays) provided that the scholar secures admission after the 20<sup>th</sup> day of a month, the amount will be made from the month following the month of admission.
- ii. In case of renewal of scholarships awarded in the previous years, maintenance charges will be paid from the month following the month up to which scholarship was paid in the previous year, if the course of study is continuous.
- iii. All scholars are expected to purchase the necessary text books, stationary etc., out of the maintenance allowance sanctioned. If it is reported by the Head of the concerned Institution that a scholar is without text-books stationary etc., the value of the scholarship may be reduced at the discretion of the authority sanctioning the scholarship.
- iv. The scholarship money will be paid to the selected students by the government of the State/Union Territory's Administration to which they belong in accordance with the procedure laid down by them in this regard.
- v. Scholarship will not be paid for the period of internship/ housemanship in the M.B.B.S. course or for a practical training in other course if the student is in receipt of some remuneration during the internship period or some allowance/stipend during the practical training in other course.
- vi. 30% of the funds allocated earmarked for girl students and 5% for students with disabilities.

- vii. Depending on availability of funds, first preference in disbursement of scholarship would be given to students of Government institutions and then to students of Government aided institutions and thereafter disbursement will be made to students of unaided private institutions.

### **VIII. MODE OF DISBURSEMENT OF SCHOLARSHIP**

In order to ensure timely payment of scholarship amount to the beneficiaries, the State Government/UT administrations are requested to avoid cash payment of scholarship amount and are required to issue instructions to all concerned that payment of scholarship should be made to beneficiaries through their accounts in post offices/banks. DBT mode should be followed by the States/UTs. Disbursement of Scholarship through Aadhaar seeded bank accounts should be ensured by the States/UTs.

### **IX. OTHER CONDITIONS FOR THE AWARD**

- i. The scholarship is provided on the basis of satisfactory progress and conduct of the scholars. If it is reported by the Head of the Institution at any time that a scholar has, by reasons of his/her own act or default, failed to make satisfactory progress or has been guilty of misconduct such as resorting to or participating in strikes, irregularity in attendance without the permission of the authorities concerned etc., the authority sanctioning the scholarships may either cancel the scholarship or stop or withhold further payment of scholarship for such period as it may think fit.
- ii. If a student is found to have obtained a scholarship by false statement his/her scholarship will be cancelled forthwith and the amount of the scholarship paid will be recovered, at the discretion of the concerned State Government. The student concerned will be blacklisted and debarred for scholarship under any schemes forever.
- iii. A scholarship awarded may be cancelled if the scholar changes the subject of the course of study for which the scholarship were originally awarded or changes the institution of study, without prior approval of the State Government. The Head of the Institution shall inform such cases to the scholar and stop payment of the scholarship money. The amount already paid may also be recovered at the discretion of the State Government.
- iv. A scholar is liable to refund the scholarship amount at the discretion of the State Government, if during the course of the year, the studies for which the scholarship has been awarded, is discontinued by him/her.
- v. The provisions of the scheme can be changed at any time at the discretion of the Government of India.

### **X. ANNOUNCEMENT OF THE SCHEME**

All the State Governments/UT Admns. will announce in the month of May-June, the details of the Scheme and invite applications by issuing an advertisement in the leading newspapers of the State and through other media outfits. All requests for application forms and other particulars should be addressed to the concerned State/UT to which students actually belong. The applicant should submit the completed application to the prescribed authority before the last date prescribed for receipt of applications.

## **V. PROCEDURE FOR APPLYING**

- i) An application for scholarship to the prescribed authority should comprise:
- a. One copy of the application for scholarship in the prescribed form (separate and 'renewal' scholarship).
  - b. One copy of the passport size photograph with signatures of the student thereon (for fresh scholarship)
  - c. One attested copy each of certificates/diploma/degree etc., in respect of all examination passed.
  - d. A certificate (in original) of Caste signed by an authorized Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
  - e. An income declaration by the parents/guardians, stating definite income from all sources by way of income certification from employer along with the affidavit on non-Judicial Stamp Paper.
  - f. A receipt in acknowledgement of the scholarship in the previous year on the form attached to the application duly countersigned by the Head of the Institution concerned, if the applicant was in receipt of a scholarship under this Scheme in the preceding year.
- ii) In case of online mode of application, the procedure of application may vary as the application is required to be filled online and the documents needs to be uploaded on the website as notified by the prescribed authority of the concerned State/UT.
- iii) Application complete in all respect shall be submitted to the Head of the Institution being attended or last attended by the candidates and shall be addressed to an officer specified for this purpose by the State Government /Union Territory Administration to which the student belongs in accordance with the instructions issued by them from time to time.

## **XII. 'FUNDS-LIMITED' NATURE OF THE REVISED SCHEME**

Due to budgetary constraint and 'funds limited' nature of the existing PMS-OBC Scheme, it is not possible for the Central Government to meet the entire demand of the States/UTs. Therefore, a Notional Allocation (NA) under the Scheme is being conveyed at the beginning of the financial year since 2008-09 to States/UTs having OBC population, in proportion to their total population as per census and they are being requested to send proposals within the notional allocation, as per the procedure outlined below:-

- i. At the beginning of the financial year, notional allocation of funds of States/UTs will be made by this Ministry, from the overall annual outlay of the Scheme, on the basis of population of each State/UT, excluding States/UTs having no notified list of OBCs (viz. Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep).
- ii. States/UTs will sub-allocate their NA, district-wise and group-wise, for all non-professional courses. Such sub-allocation would not be necessary for professional courses, as institutions of professional education tend to be concentrated in major cities/centres. However, the State Government is expected to lay down criteria for selection for award of scholarship under both types of courses, professional and non-professional, to the extent of available funds, based on merit-cum-means.
- iii. States will earmark at least 25% of the total outlay under the Scheme for Group D courses which include Class-XI and XII and all other post-matriculation level non-

degree courses, diploma courses in polytechnics etc. Such earmarking would encourage more OBC students to join entry-level courses of tertiary education which would enable them subsequently to take up courses leading to higher qualifications.

- iv. Central assistance given to a State/UT would have to be first utilized to cover renewal cases (i.e. students already awarded scholarships during the previous years against Central Assistance), and only the balance amount left may be utilized to cover new cases.
- v. The proposal for Central Assistance should be accompanied with the details of physical and financial progress in the prescribed performa.
- vi. As the total demand of the States/UTs cannot be covered under the Central Assistance, the States/UTs shall provide remaining scholarship grants to the eligible students from their own budget.

### **XIII. FUNDING PATTERN OF THE SCHEME**

The Scheme is being implemented by the State Governments and Union Territory Administrations, which receive central assistance from Government of India under the Scheme. The concept of Committed Liability will not apply to States/UTs from the year 2018-19 onwards. States/UTs are liable to make provisions for funds over and above Central Assistance to cover all eligible students.

### **XIV. MONITORING**

The monitoring of the financial and physical performance of the Scheme will be done through seeking detailed information from the agencies implementing the Scheme and for the physical aspects the agencies implementing will be required to furnish Quarterly Progress Reports regarding the number of beneficiaries receiving award under the Scheme, both class-wise and gender-wise. On the financial side, details of actual expenditure incurred during the last financial year and expenditure proposed for the present financial year will be submitted by the agencies concerned. The agencies implementing the scheme will also be insisted upon to submit the latest audited accounts.

### **XV. EVALAUTION**

The Ministry of Social Justice & Empowerment will get the scheme evaluated by entrusting a research study to reputed institutions/agencies, on the performance of the Scheme in different parts of the country, under this Ministry's Scheme of Research and Training.

\*\*\*\*\*